**[2023] 14 एस.सी.आर. 230: 2023 आईएनएससी 988**

**वाद का विवरण**

कर्नाटक राज्य

बनाम

टी. नासिर @नासिर @तंजानटविंडा नासिर @उमरहाज़ी @हाजी एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 3456/2023)

06 नवंबर, 2023

**[विक्रम नाथ और राजेश बिंदल, न्यायमूर्तिगण]**

**शीर्ष टिप्पणियाँ**

**विचारणीय मुद्दा**: उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में दायर आवेदनों को खारिज कर दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा का 311, अभियोजन साक्ष्य-189 को वापस बुलाने और अभियोजन को रिपोर्ट और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख।

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311- साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 65ख- एक सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ- कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया- विचारण न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साक्ष्य में अस्वीकार्य ठहराया- इसके बाद, अभियोजन पक्ष को अभियोजन साक्ष्य- 189 को वापस बुलाने और साक्ष्य अधिनियम का 65ख का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया गया। -विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए गए आवेदन को विलंबित मानते हुए-उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा- औचित्य:**

**अभिनिर्धारित**: निचली अदालतों ने गलत आधार पर यह राय दी थी कि प्रमाण पत्र पेश करने में छह साल की देरी हुई थी, जबकि ऐसा नहीं था- मामला तब भी लंबित था जब अभियोजन साक्ष्य- 189 को फिर से तलब करने और साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख प्रमाण पत्र पेश करने का आवेदन था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 वास्तव में, दिनांक 29.11.2010 को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सामग्री के आधार पर सीएफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट

पहले ही दिनांक 16.10.2012 को विचारण न्यायालय के समक्ष रखी गई थी- यह केवल दिनांक 07.04.2017 के आदेश के माध्यम से था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को धारा 65ख द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर लेने से इनकार कर दिया गया था। अभियोजन साक्ष्य- 189 की मुख्य परीक्षा की जांच के दौरान सीएफएसएल की रिपोर्ट दिनांक 29.11.2010 को प्रदर्शित करने की मांग की गई थी- जब उपरोक्त गवाह की दिनांक 27.04.2017 को मुख्य रूप से जांच की गई थी, तो प्रतिवेदन साक्ष्य अधिनियम की धारा धारा 65ख प्रस्तुत किया गया था जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति उठाई गई थी और दिनांक 20.06.2017 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेने से इनकार कर दिया, अभिलेख पर लेने से- इसके बाद एक आवेदन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दर्ज किया गया था, अभियोजन साक्ष्य -189 को वापस बुलाने और साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए ताकि उसे अभिलेख पर लिया जा सके। इसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था- उपरोक्त तथ्यों से, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में छह वर्ष की देरी हुई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई है, वह कोई साक्ष्य नहीं है जो अब बनाया गया है- यह अभिलेख पर एक रिपोर्ट को साबित करने के लिए कानून की आवश्यकता को पूरा कर रहा है- अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देकर। इस स्तर पर अधिनियम के 65ख के परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति कोई अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होगा- अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य का खंडन करने का पूरा अवसर होगा। [अनुच्छेद12,13,14 और 15]

**उद्धरणो और अन्य संदर्भों की सूची**

अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473: [2014] 11 एससीआर 399; अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल, (2020) 7 एससीसी 1: [2020] एससीआर 180; कर्नाटक राज्य बनाम एम. आर. हिरेमथ, 2019 (7) एससीसी 515: [2019] 8 एससीआर 713-पर भरोसा किया।

**आक्षेपित आदेश और उपस्थिति सहित अन्य मामले का विवरण**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 3456/2023 सीआरएलपी संख्या 2585/2019 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 27.01.2022 के निर्णय और आदेश से।

**अधिवक्तागण**:

अमन पंवार, एएजी, शिवम सिंह बघेल, डी. एल. चिदानंद, अपीलार्थियों के लिए।

बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री सुकन्या जोशी, हैरिस बीरन, अजहर असीस, आनंद बी. मेनन, राधा श्याम जेना, प्रतिवादियों के लिए।

**सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**निर्णय**

**राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति।**

1. अनुमति दी गई।

2. आपराधिक याचिका संख्या[1] में उच्च न्यायालय[2] द्वारा पारित आदेश 2585/2019 के माध्यम से। अपीलार्थी- राज्य के नेतृत्व में, विचारण न्यायालय[3] द्वारा पारित दिनांक 18.01.2018 के आदेश को बरकरार रखा गया था। उपरोक्त आदेश के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता[5] की धारा 311 के तहत अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में एक आवेदन[4], जिसमें एम. कृष्णा (अभियोजन साक्ष्य -189) को वापस बुलाने और अभियोजन पक्ष को रिपोर्ट पेश करने की अनुमति देने की मांग की गई थी और अधिनियमकी धारा 65 ख के तहत प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया था।

3. वाद की उत्पत्ति यह है कि दिनांक 25.07.2008 को बैंगलोर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में एक महिला की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हो गए। मादीवाला[7], कोरमंगला[8], ब्याटारायनपुरा[9], केंगेरी[10], अशोकनगर[11], सम्पंगीरामा[12] और अदुगोडी[13] पुलिस स्टेशनों में भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख , 121,121क , 123,153क , 302,307,326,337,435,506 और 201 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 से 6, विनाश और संपत्ति की हानि निवारण अधिनियम, 1981 की धारा 3 और 4, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की

रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। इस दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि एक लैपटॉप, एक बाहरी हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 5 फ्लॉपीज, 13 सीडी, 6 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, एक मेमोरी कार्ड और 2 डिजिटल कैमरा आदि जांच की प्रक्रिया में आरोपी संख्या 3, जो, सरफराज नवाज @सेजू @हकेम के इशारे पर जब्त किया गया था। मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दिनांक 09.06.2010 के अतिरिक्त आरोपपत्र के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। निचली अदालत ने दिनांक 07.04.2017 के आदेश के माध्यम से आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संदर्भ में दिनांक 29.11.2010 की सीएफएसएल रिपोर्ट अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य में अस्वीकार्य थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, मूल उपकरण पहले से ही अभिलेख में हैं (प्राथमिक साक्ष्य के रूप में) अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए अधिनियम की धारा 65-ख के तहत एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था और जब दिनांक 27.04.2017 को एम. कृष्णा (अभियोजन साक्ष्य -189) की मुख्य रूप से जांच की गई, तो अधिनियम की धारा 65-ख के तहत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। अभियुक्त के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई थी। दिनांक 20.06.2017 के आदेश के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने राय दी कि दिनांक 27.04.2017 को प्रस्तुत अधिनियम की धारा 65-ख के तहत जारी प्रमाण पत्र साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं था। इसके बाद अभियोजन पक्ष को एम. कृष्णा (अभियोजन साक्ष्य -189) को वापस बुलाने और साक्ष्य में अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र पेश करने की अनुमति देने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया गया। निचली अदालत ने आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें देरी हो रही है। निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। यह उपरोक्त आदेश है जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

4. अपीलार्थी- राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अमन पंवार ने अपने संक्षिप्त तर्क में कहा कि पूरे देश को झकझोर देने वाले मामले में बैंगलोर में सिलसिलेवार बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड आरोपी था। निचली अदालतों को इस संदर्भ में आवेदन पर विचार करना चाहिए था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिसे पेश करने की मांग की गई थी, वह कुछ ऐसा नहीं था, जिसे बाद में बनाया गया था। बल्कि यह अधिनियम की धारा 65 ख के तहत केवल एक प्रमाण पत्र था। सीएफएसए की रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रूप में प्राथमिक

साक्ष्य पहले से ही अभिलेख  में था। यह केवल इसलिए है क्योंकि आरोपी ने उस रिपोर्ट को पेश करने पर आपत्ति जताई और कोई जोखिम नहीं लिया, अभियोजन पक्ष ने धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन का नेतृत्व किया। एम. कृष्णा (अभियोजन साक्ष्य -189) को फिर से समन करना और साक्ष्य में अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2017 को सीएफएसएल की दिनांक 29.11.2010 की रिपोर्ट को खारिज करने के तुरंत बाद कोई देरी नहीं हुई थी, दिनांक 16.12.2017 को एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें अधिनियम की धारा 65 ख के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। निचली अदालतों को इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए थी कि अधिनियम की धारा 65-ख के तहत अभियोजन पक्ष को प्रमाण पत्र पेश करने का अवसर देने से इनकार करने से अपीलार्थी के साथ बहुत अन्याय होगा। इन तर्कों के समर्थन में कि अधिनियम की धारा 65-ख के तहत एक प्रमाण पत्र कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत/प्रस्तुत किया जा सकता है, **अनवर पी. वी.  बनाम पी. के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473: [2014] 11 एससीआर 399; अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल, (2020) 7 एससीसी 1** में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया था।

5. जवाब में, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता  श्री बालाजी श्रीनिवासन ने कहा कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं थी। अभियोजन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन के माध्यम से साक्ष्य में कमी को दूर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। छह साल की देरी के बाद प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। इसलिए, इसे अभिलेख  पर पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो अब प्रतिवादियों के लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा होगा। प्रतिवादियों को निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित किया जाएगा। याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

6. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और प्रासंगिक संदर्भित अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. पिछले अनुच्छेद  में मामले के तथ्यों पर संक्षिप्त रूप से ध्यान दिया गया है। बैंगलोर में दिनांक 25.07.2008 को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों ने न केवल बैंगलोर शहर और राज्य बल्कि पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि इस तरह के आतंकवादी हमलों में केवल निर्दोष लोग

ही पर्याप्त होते हैं। जाँच वैज्ञानिक होनी चाहिए। आरोपी संख्या 3 के इशारे पर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि एक लैपटॉप, एक बाहरी हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 5फ्लॉपीज , 13 सीडी, 6 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, एक मेमोरी कार्ड और 2 डिजिटल कैमरा आदि बरामद किया गया और जब्त कर लिया गया। इन्हें जाँच के लिए सीएफएसएल हैदराबाद भेजा गया था। रिपोर्ट 29.11.2010 को प्राप्त हुई थी। उसी को दिनांक 16.10.2012 को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और बयान दर्ज करने के समय एम कृष्णा, सहायक सरकारी परीक्षक, कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीजन, सीएफएसएल, अभियोजन साक्ष्य- 189 के रूप में पेश हुए। अभियुक्त ने दिनांक 06.03.2017 के आवेदन के माध्यम से अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य में दिनांक 29.11.2010 की रिपोर्ट लेने पर आपत्ति जताई। इसके तुरंत बाद, अधिनियम की धारा 65-ख के तहत दिनांक 27.04.2017 को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया गया। एम. कृष्णा (अभियोजन साक्ष्य -189) को वापस बुलाना और साक्ष्य में उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। मुकदमा अभी भी लंबित था। विद्वत विचारण न्यायालय ने इस संबंध में कानूनी स्थिति की सराहना किए बिना आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। यह मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 65 ख के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी के कारण था।

8. **अनवर के मामले (उपर्युक्त)** में इस न्यायालय ने राय दी है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उपयोग प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है तो अधिनियम की धारा 65ख के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रासंगिक अनुच्छेद को नीचे उद्धृत किया गया हैः

**"24.** यदि अपीलार्थी घोषणा और गीतों के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को साक्ष्य में उपलब्ध कराकर प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करता तो स्थिति अलग होती। यदि आपत्तिजनक गीतों या घोषणाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को पुलिस या चुनाव आयोग के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया जाता और उसी का उपयोग प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता, तो उच्च न्यायालय यह देखने के लिए अदालत में ऐसा ही कर सकता था कि क्या आरोप सही थे। इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। भाषणों, गीतों और घोषणाओं को अन्य उपकरणों का उपयोग करके अभिलेख  किया जाता था और उन्हें एक कंप्यूटर में फीड करके, सीडी बनाई जाती थी, जिन्हें बिना किसी प्रमाण के अदालत में पेश किया जाता था। उन सीडी को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख

की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। **यह स्पष्ट किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 59,65-क और 65-ख के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के द्वितीयक साक्ष्य पर हमने पूर्ववर्ती अनुच्छेद में जो कुछ कहा है, उसके बावजूद, यदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-ख की शर्तों के अनुपालन के बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है।**

(जोर दिया गया)

9. उपरोक्त मुद्दे पर बाद में इस न्यायालय द्वारा **अर्जुन पंडितराव खोटकर (ऊपर)** के मामले में विचार किया गया था और यह राय दी गई थी कि कंप्यूटर में निहित मूल जानकारी और उससे बनाई गई प्रतियों के बीच एक अंतर है। पहला प्राथमिक साक्ष्य है और दूसरा द्वितीयक साक्ष्य है। अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र अनावश्यक है जब मूल दस्तावेज (जो., प्राथमिक साक्ष्य) स्वयं प्रस्तुत किया जाता है। इसके प्रासंगिक अनुच्छेद '33' को नीचे निकाला गया हैः

**"33.** "33. उपधारा (1) में अबाधित खंड यह स्पष्ट करता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट सूचना की बात आती है तो उसकी ग्राह्यता और प्रमाण धारा 65-ख की कवायद का अनुसरण करना चाहिए, जो इस निमित्त एक विशेष उपबंध है-धारा 62 से 65 इस प्रयोजन के लिए अप्रासंगिक है। **हालांकि, धारा 65-ख (1) स्पष्ट रूप से "मूल" दस्तावेज़ के बीच अंतर करती है- जो "कंप्यूटर" में निहित मूल "इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख " होगा जिसमें मूल जानकारी पहले संग्रहीत की जाती है- और ऐसी जानकारी वाले कंप्यूटर आउटपुट, जिसे तब "मूल" दस्तावेज़ की सामग्री के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। यह सब अनिवार्य रूप से दर्शाता है कि धारा 65-ख "कंप्यूटर" में निहित मूल जानकारी और उससे बनाई गई प्रतियों के बीच अंतर करती है-पहला प्राथमिक साक्ष्य है, और दूसरा द्वितीयक साक्ष्य है।**

(जोर दिया गया)

10. **कर्नाटक राज्य बनाम एम. आर. हीरेमथ, 2019 (7) एससीसी 515,** के मामले में इस न्यायालय ने **अनवर के मामले (उपर्युक्त)** में पूर्व निर्णय का निर्देश करने के पश्चात् यह

अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 65ख के अधीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना एक उपचारी दोष है। इसके प्रासंगिक अनुच्छेद '16' को नीचे निकाला गया हैः

"16. इसी विचार को भारत संघ बनाम रवींद्र वी. देसाई, (2018) 16 एससीसी 273 में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दोहराया गया है। **न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पहले के अवसर पर धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना एक उपचार योग्य दोष है।** न्यायालय ने सोनू बनाम हरियाणा राज्य (2017) 8 एससीसी 570 में पहले के निर्णय पर भरोसा किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

'32 ... महत्वपूर्ण परीक्षण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कहा गया है, यह है कि क्या दस्तावेज़ को चिह्नित करने के चरण में दोष को ठीक किया जा सकता था। इस परीक्षण को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, यदि सीडीआर को प्रमाण पत्र के बिना चिह्नित किए जाने पर आपत्ति जताई जाती, तो अदालत अभियोजन पक्ष को अवज्ञा को सुधारने का अवसर दे सकती थी।

(जोर दिया गया)

11. अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र के मुद्दे पर इसके प्रस्तुतीकरण के चरण के रूप से संबंधित है, **अर्जुन पंडितराव खोटकर के मामले में इस अदालत (ऊपर)** माना जाता है कि प्रमाण पत्र अधिनियम के 65-ख के तहत किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है अगर परीक्षण खत्म नहीं होता है। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे निकाले गए हैं:

**"56.** इसलिए, सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जिन पर मुकदमा शुरू होने से पहले अभियुक्त को भरोसा दिया जा सकता है। इस प्रकार, आपराधिक विचारणों में न्यायालयों द्वारा साक्ष्य को बाद के चरण में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में शक्ति के प्रयोग का परिणाम अभियुक्त के प्रति गंभीर या अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में एक संतुलन अभ्यास न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, अभियोजन द्वारा किसी भी आवेदन की जांच करने में धारा 91 या 311 सीआरपीसी या साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत। **प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और न्यायालय यह देखने के बाद विवेकाधिकार का प्रयोग**

**करता है कि अभियुक्त निष्पक्ष विचारण के अभाव में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, न्यायालय उपयुक्त मामलों में अभियोजन पक्ष को बाद में ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। यदि यह अभियुक्त है जो अपने बचाव के हिस्से के रूप में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो यह फिर से मामले के न्याय पर निर्भर करेगा-अदालत द्वारा कानून के अनुसार विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना।**

59. ऊपर दिए गए अनुच्छेद 52 और 56 में दी गई चेतावनी के अधीन, इन दोनों उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित विधि में हमारी सहमति है। **जब तक किसी मुकदमे में सुनवाई अभी तक समाप्त नहीं हुई है, अपेक्षित प्रमाण पत्र को किसी भी स्तर पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रपत्र में निहित जानकारी को तब स्वीकार किया जा सके और साक्ष्य में भरोसा किया जा सके।**

(जोर दिया गया)

12. निचली अदालतों ने गलत आधार पर यह मत व्यक्त किया था कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में छह साल की देरी हुई थी, जबकि कोई देरी नहीं हुई थी। मामला तब भी लंबित था जब एम कृष्णा (पीडब्लू-189) को फिर से बुलाने और अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आवेदन दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 311 के तहत किया गया था।

13. यह केवल 07.04.2017 के आदेश के माध्यम से था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर लेने से इनकार कर दिया गया था। मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पहले से ही साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था और एमओ के रूप में चिह्नित किया गया था। यह एम कृष्णा (पीडब्लू-189) के मुख्य जांच जांच के दौरान था कि सीएफएसएल की रिपोर्ट दिनांक 29.11.2010 को प्रदर्शित करने की मांग की गई थी। हालांकि, विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.04.2017 के आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 65ख के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में इसे अभिलेख पर लेने से इनकार कर दिया। जब उपर्युक्त साक्षी से 27.04.2017 को मुख्य परीक्षा से और पूछताछ की गई, तो धारा 65ख के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जताई गई और दिनांक 20.06.2017 के आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 65ख के अधीन जारी प्रमाण पत्र को अभिलेख पर लेने से

इनकार कर दिया। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) को वापस बुलाने और अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए। उसी को निचली अदालत द्वारा दिनांक 18.01.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

14. उपर्युक्त तथ्यों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में छह साल की देरी हुई थी। वास्तव में, दिनांक 29.11.2010 को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सामग्री के आधार पर सीएफएसएल, हैदराबाद से प्राप्त रिपोर्ट पहले ही दिनांक 16.10.2012 को विचारण न्यायालय के समक्ष रखी गई थी। वास्तव में, अभियोजन पक्ष का रुख यह था कि जब मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन पहले से ही किया जा चुका था और एमओ को चिह्नित किया गया था, तो अधिनियम की धारा 65-ख के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी, पर्याप्त सावधानी के रूप में, उसी को प्रस्तुत किया गया था, वह भी जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर तैयार की गई सीएफएसएल रिपोर्ट के प्रस्तुति के खिलाफ अभियुक्त द्वारा आपत्ति उठाए जाने के तुरंत बाद।

15. आपराधिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि यह किसी एक पक्ष के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। बल्कि, उद्देश्य यह है कि कोई भी दोषी निर्दोष न रहे और किसी भी निर्दोष को दंडित न किया जाए। अधिनियम की धारा 65-ख के तहत एक प्रमाण पत्र, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पेश करने की मांग की गई है, वह सबूत नहीं है जो अब बनाया गया है। यह अभिलेख पर एक रिपोर्ट साबित करने के लिए कानून की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अभियोजन पक्ष को इस स्तर पर अधिनियम की धारा 65 ख के तहत प्रमाण पत्र पेश करने की अनुमति देने से अभियुक्त के प्रति कोई अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होगा। अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य का खंडन करने का पूरा अवसर होगा। यह उद्देश्य जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 है। वहाँ है। संहिता का उद्देश्य सत्य तक पहुँचना है। हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत शक्ति, न्याय और लोक हित के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। साथ में मामले में, सच्चाई को बनाए रखने के लिए शक्ति के इस प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आरोपी के प्रति इस तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होने वाला है।

16. उपर्युक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है। निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों

को दरकिनार कर दिया गया है। नतीजतन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में आवेदन की अनुमति है। निचली अदालत मामले पर आगे बढ़ेगी।

शीर्ष टिप्पणियाँ अंकित ज्ञान द्वारा तैयार की गईं। अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक (मदन मोहन प्रिय) के द्वारा किया गया है।